1	2	3	4	5	6
3.	महानदी डेल्टा चरण – II	6/92	34.52	1036.0	89.0
	कुल		68.86	2186.0	634.2
छ.	**राजस्थान**				
1.	बुचारा	7/94	2.02	79.0	-
2.	घील	7/94	6.50	219.0	-
3.	गुडहा	7/94	10.39	450.0	-
4.	जेतपुरा	7/94	3.73	123.0	-
5.	नंद सामंद	7/94	7.00	242.0	-
6.	उरई	7/94	9.26	414.0	-
7.	सैंघल	7/94	3.27	127.0	-
8.	उंमेद सागर	7/94	2.97	134.0	-
	कुल		46.10	1788.0	-
ज.	**तमिलनाडु**				
1.	चित्तार	6/92	9.64	241.0	670.3
2.	मंजलार	1/93	2.17	54.0	127.7
3.	पिल्लावुक्कल	1/93	3.60	91.0	-
	कुल		15.14	386.0	798.0

उ0स0= उच्च स्तरीय

पेट्रो-रसायन संयंत्र में दुर्घटना

2730. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या **रसायन और उवर्क** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या गुजरात में हजीरा स्थित रिलायंस औद्योगिक समूह के पेट्रो-रसायन संयंत्र में हाल ही में एक भीषण दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना में कितने मजदूरों की मृत्यु हुई और कितने मजदूर घायल हुए;

(घ) इस भीषण दुर्घटना के क्या कारण है; और

(ड) क्या उपर्युक्त औद्योगिक समूह ने प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को उचित और पर्याप्त मात्रा में मुआवजे का भुगतान किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ड) जानकारी एकत्रित की जायेगी और सभा के पटल पर रखी दी जाएगी

भोपाल गैस त्रासदी के शिकार हुए लोगों को अन्तरिम राहत

2731. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या दिसम्बर, 1984 में कीटनाशक संयंत्र से एम0आई0सी0 गैस रिसने से प्रभावित हुए भोपाल शहर के सभी बाड़ों को अन्तरिम सहायता दी गई है;

(ख) यदि नहीं तो कितने बार्डो को यह राहत दी गई है और कितने बोर्ड ऐसी राहत से वंचित रह गये हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने शेष सभी वार्ड़ो को अन्तरिम राहत दिए जाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है; यदि हां, तो कब; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है और यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तो अन्तरिम राहत की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरियो) : (क) से (घ) भोपाल शहर के गंभीर रूप से प्रभावित 36 बार्डो में अन्तरिम सहायता दी जा रही है । मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य 20 वार्डो में भी अन्तरिम सहायता देने के लिए अनुरोध किया है । अन्तरिम सहायता देने के लिए अनुरोध किया है । अन्तरिम सहायता उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दी जा रही है ।

Setting up of Committee of Commission with minister's Approval

2732. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH.

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have decided that no new committee or commission be set up without the specific approval of the HRD Ministry;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of committees or commissions at present functioning under the Union Government; and

(d) the details of expenditure incurred on these committees/commissions during each of the last three years?

THE MINISTER OF STATE DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OF CULTURE (KUMARI SELIA): (a) and (b) No, Sir. However, Ministry of Finance has decided that there should be a complete freeze on setting up of new Committees/ Commissions. Specific approval of the Group of Ministers would be required before any new Committee/Commission is set up.

(c) and (d) The Ministry do not maintain centralised data regarding the number of Committees/Commissions set up by various Ministries/Departments.

Scholarships for the welfare of the Children of Scavengers

2733. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have announced some scholarships for children whose parents are engaged in scanvenging of dry latrines, sweepering, tanning and flaying, considered unclean;

(b) if so, the details of such scholarships, with categories of people to be benefited with them;

(c) whether some eligibilities have been fixed for such scholarships;

(d) whether parents and students have to undergo some formalities to get such scholarships;

(e) whether some rates of scholarships have also been fixed; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) The Centrally sponsored Scheme of Pre-Matric Scholarships to children of those engaged in unclean occupations is being implemented through State Government/ Union Territory Administrations since 1977-78 to promote pre-matric education among such children.

(b) This Scheme provides financial assistance on a matching basis to specific categories of children of scavengers of dry latrines, tannere, flayers and sweepers irrespective of their religion, who have traditional links with scavenging. The Scheme provides scholarships for hostellers in Classes III to X and for day-scholars from Classes I to X. X.

(c) Yes, Sir. The specific eligibility conditions are given below:

(i) A certificate is required from the candidate each- year to the effect that at least one parent is still engaged in unclean occupation as defined in the Scheme.